प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन या बैंकिंग कम्पनी, खान, तेल क्षेत्र या मुख्य पत्तन के संबंध में या किसी निगम के संबंध में, जिसे केन्द्रीय सरकार के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो, किसी नियोजन के संबंध में समुचित सरकार है। इन क्षेत्रों में समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन की जिम्मेदारी मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को सौंपी गई है। समान पारिश्रमिक अधिनियम के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र के भीतर आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में किए गए निरीक्षणों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

राज्य क्षेत्र में अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में, छह राज्य सरकारों ने महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए महिला सेलों की स्थापना की है।

केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गई है जिसमें नियोक्ताओं और कर्मकारों, संसद सदस्यों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। सलाहकार समिति सरकार को इस संबंध में सलाह देने के लिए समय-समय पर बैठकें करती है कि महिलाओं को किस हद तक नियोजित किया जाए, कार्य घंटे क्या हों, रोजगार में महिलाओं का स्थायित्व क्या हो, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की आवश्यकता और अंशकालिक रोजगार आदि। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए 21 राज्य सरकारों द्वारा भी इसी तरह के निकायों का गठन किया गया है।

विवरण

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की स्थिति (संख्या में)

	निरीक्षण	पाए गए उल्लंघन	ठीक किए गए उल्लंघन	चलाए गए अभियोजन	सिद्ध दोष	छोड़ दिए गए
केन्द्रीय						
1995*	4367	4359	4229	1054	748	8
1996*	4468	4373	4702	927	741	39
1997*	4195	4722	4187	1110	586	35

*आंकड़े अनंतिम हैं।

Welfare of street Children in Gujarat

*580. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether Government are implementing any scheme for the welfare of the street children in the State of Gujarat;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what assistance is being extended by the State Government in the Implementation of the scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Ministry is supporting 3 Non-Governmental Organisations at Ahmedabad and 2 Non Governmental Organisations at Baroda in the State of Gujarat under the Scheme of Welfare of Street Children.

(c) Under the Scheme, 90% of the Project cost is met by the Government of India and the remaining 10% by the concerned Non-Governmental Organisation and as such no financial assistance is provided by the State Government.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

Workers of Coal India Limited

4282. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) how many workers job was terminated due to superannuation in the year 1996 and 1997 in Coal Producing Company of Coal India Limited;